वार्षिक विवरण 2022–23

बजट अध्ययन एवं अनुसन्धान केंद्र ट्रस्ट

Budget Analysis and Research Centre Trust

(www.barctrust.org)

Banwari Niwas, Plot No. 44, Roop Nagar, Hari Marg, Civil Lines, Jaipur, Rajasthan, India - 302006

विषय–वस्तु

बार्क ट्रस्ट : परिचय	2
दृष्टि और लक्ष्य	3
बार्क ट्रस्ट के उद्देश्य	4
मुख्य कार्यक्षेत्र	5
प्रमुख गतिविधियां	6
2022–23 के दौरान की गतिविधियां	7
I. बजट एडवोकेसी	7
II. शोधपरक अध्ययन	9
III. संगोष्ठियां और कार्यशालाएं	11
IV. साझेदारी और नेटवर्किंग	12
V. बार्क ट्रस्ट एक रिसोर्स सेंटर के रूप में	13
VI. वेबसाइट	14
VII. प्रमुख उपलब्धियां	
VIII. निष्कर्ष	
संलग्न	

बार्क ट्रस्ट : परिचय

बजट एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर (बार्क) ट्रस्ट एक स्वतंत्र संस्था है, जो सरकार की नीतियों और बजट के गहन विश्लेषण के द्वारा शासन में पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।

अधिकारिक रूप से बार्क ट्रस्ट 4 मार्च 2015 को एक ट्रस्ट के रूप पंजीकृत किया गया। बार्क का लक्ष्य सरकारों के बजट का विश्लेषण करना, यह आकलन करना कि सरकार का बजट नीतिगत दस्तावेजों, चुनावी घोषणाओं, बजट भाषणों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं व प्रशिक्षण और प्रकाशनों में की गई वितीय प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त है या नहीं।

बार्क ट्रस्ट एक तरह से बजट एनालिसिस राजस्थान सेंटर (बार्क) का नया रूप है, जिसे बजट और नीतिगत शोध व कार्य आगे बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया। बार्क ट्रस्ट को अधिकारिक रूप से एक ट्रस्ट के रूप में 4 मार्च 2015 को पंजीकृत किया गया था। मूल रूप से बार्क सन् 2003 में बजट अध्ययन एवं नीतिगत शोध केन्द्र सेंटर के रूप में स्थापित किया जा चुका था जिसका उद्देश्य केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तरों पर सरकार के बजट और नीतियों का विश्लेषण करना और यह जांचना था (नीतिगत दस्तावेजों, चुनाव घोषणापत्र, बजट भाषण और अंतर्राष्ट्रीय मंचों) में किये गए वचनों से बजट के वितीय प्रावधान मेल खाते हैं या नहीं।
बार्क ट्रस्ट राज्य के बजट के बजट का गरीबों और वंचितों की दृष्टि से विश्लेषण करने में भागीदार रहा है और इसने अपने विश्लेषण का उपयोग हाशिये के समुदाय जैसे कि दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और बच्चों के मुद्दों व चिंताओं को आगे बढाने के लिए करता रहा है।

दृष्टि (विज़न)

बार्क ट्रस्ट का विज़न एक ऐसे नीतिगत परिवेश का है जिसमें सभी के अधिकार, न्याय और कल्याण सुनिश्चित हो, विशेषकर वंचित व हाशिये के लोगों के जैसे कि दलित, आदिवासी, महिलाएं, बच्चे, अल्पसंख्यक और भिन्न रूप से सक्षम लोग। बार्क ट्रस्ट सिविल सोसायटी, सरकार और मीडिया के साथ मिलकर जनपक्षधर नीतियां और बजट प्रक्रिया बनवाने का प्रयास करते हैं।

उद्देश्य

बार्क ट्रस्ट का उद्देश्य जनता के बड़े हिस्से के लिए जटिल बजटीय आंकड़ों और प्रमुख नीतिगत मामलों को सरल बनाना, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना तथा सरकारी और गैर–सरकारी विकास के कार्यक्रमों तक हाशिये के समुदायों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उनकी क्षमताओं में वृद्धि करना है।

बार्क ट्रस्ट के उद्देश्य

शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना।

सार्वजनिक बजट और उसकी प्रक्रियाओं को व्यापक जनता के लिए समझने योग्य बनाना।

सरकारी और गैर–सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों तक हाशिये की समुदायों की पहुंच सुगम बनाना।

व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए उनके साथ मिलाकर कार्यशालाओं और क्षमतावृद्धन कार्यक्रम आयोजित करना

भारत और/या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठनों के साथ समन्वय और सहयोग करके नेटवर्क बनाना जो गरीबों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा

किसी व्यक्ति, संस्था, सरकार या गैर सरकारी अन्य सामान्य संस्थाओं को कार्य शुरु करने और विस्तार देने के क्षेत्र में सलाह प्रदान करना

संसाधन केंद्र और दस्तावेज़ीकरण केंद्र विकसित करना जो शासन और नीति में जन शिक्षा और जवाबदेही को बढ़ावा देंगे

आंकड़ो विश्लेषण, प्रशिक्षण आदि में सलाह (कॉन्सलटेन्सी) देना।

मुख्य कार्यक्षेत्र

1. बजट, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. स्थानीय स्वशासी संगठन

3. हाशिये के समूह

- बच्चे
- महिलाएं
- विशेष योग्यजन
- दलित
- आदिवासी
- वरिष्ठ नागरिक
- अल्पसंख्यक
- असंगठित श्रमिक
- शहरी गरीब

4. सामाजिक क्षेत्र

- स्वास्थ्य
- शिक्षा
- पेयजल एवं स्वच्छता
- सामाजिक सुरक्षा

- पोषण एवं खाद्य सुरक्षा

5. ग्रामीण अर्थव्यवस्था

- कृषि
- सिंचाई
- रोजगार
- आवास

6. ऊर्जा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

प्रमुख गतिविधियां

नीति विश्लेषण और अनुसंधान
बजट विश्लेषण और पैरवी
स्थानीय स्वशासी निकायों का बजट और योजना
क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण
कार्यशालाएँ और सेमिनार
साझेदारी और नेटवर्किंग
निगरानी और मूल्यांकन

प्रकाशन

गतिविधियाँः 2022–23

बजट एडवोकेसी

बार्क ट्रस्ट केंद्र और राज्य के बजट का विश्लेषण करता है तथा बजट की तैयारी और कार्यान्वयन के संबंध में पारदर्शी, जवाबदेह और सहभागी शासन व जन केंद्रित परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बजट से पूर्व और बजट के बाद की एडवोकेसी करता है।

❖ बजट पूर्व पैरवी

हर साल बार्क ट्रस्ट बजट प्रक्रिया के बारे में लोगों की समझ और भागीदारी बढ़ाने के लिए बजट–पूर्व–पैरवी करता है। बजट–पूर्व–पैरवी में राजस्थान सरकार के साथ गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ), समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ), यूनियनों और पूरे राजस्थान में काम करने वाले संगठनों को शामिल करके की जाती है।

इसमें केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर आगामी बजट के लिए सुझाव देने और अपनी मांगें उठाने के लिए राजस्थान के विधानसभा सदस्यों (विधायकों) के साथ एक पूर्व–बजट कार्यशाला का आयोजन भी किया जाता है। राज्य के गैर–सरकारी संगठनों और सिविल सोसायटी के साथ बजट–पूर्व–परामर्श भी आयोजित किये जाते हैं। बार्क ट्रस्ट ने पीपुल्स बजट इनिशिएटिव (पीबीआई) द्वारा आयोजित केंद्र सरकार के साथ केंद्रीय बजट पर बजट–पूर्व–एडवोकेसी में सक्रिय रूप से भाग लिया।

❖ बजट पूर्व परामर्श

राजस्थान सरकार के बजट पूर्व परामर्श में भागीदारीः बार्क ट्रस्ट ने सीएसओ से सुझाव लेने के

Rajasthan Budget 2023-24: Announcements Useful and Aplenty, Will There be Effective Implementation?

Nesar Ahmad | 12 Feb 2023 Economy India

The state government has been able to make a number of Budget announcements for every section of society in the election year, while still keeping the fiscal deficit under the 4% limit.

Image credit: PTI

The last Budget of the current regime of the Rajasthan government, as expected, is full of announcements for everyone. The state Budget has been in limelight for months and by putting up hoardings with the words "Saving, Relief, Growth", the state government had raised people's expectations. This year, the government

घोषणाओं का क्रियान्वयन बड़ी चुनौती

राजस्थान सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट जैसा कि आशा थी, सभी वर्गों के लिए घोषणाओं से भरा है। सरकार ने पहले ही बजट को चर्चा के केंद्र में ला दिया था और 3 दिन पहले सरकार ने -बचत, राहत, बढ़त- के बड़े-बड़े बोर्ड लगाकर जन अपेक्षाओं को और बढ़ा दिया था। इस बजट में जहां एक तरफकिसानों के लिए 1000 से बढ़ा कर 2000 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की वहीं घरेलू उपभोक्ताओं के मुफ्त बिजली की सीमा 50 यूनिट से बढ़ा कर 100 यूनिट तक कर दी। उज्जवला योजना के लाभार्थियों के लिए 500 रुपए में रसोई गैस की टंकी की भी घोषणा हुई। इसके अलावा युवाओं के लिए कई घोषणाएं हुई हैं जैसे नौकरियों के लिए परीक्षाओं की फीस माफी, शोधरत छात्रों के लिए 3 वर्ष तक 20 हजार रुपए प्रतिमाह का फेलोशिप और युवाओं के लिए नई नीति की घोषणा महत्वपूर्ण हैं। वहीं सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन की राशि में बढ़ोतरी (शेष पृष्ठ 13 कालम 1 पर)

नेसार अहमद
निदेशक, बजट एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर

लिए 10 नवंबर, 2022 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के बजट पूर्व परामर्श में भाग लिया और राज्य के बजट 2023–24 के लिए हमारे सुझाव देकर मांगों का एक चार्टर प्रस्तुत किया। .

❖ बजट के बाद की गतिविधियाँ

बजट विश्लेषण

2022–23 के बजट पर प्रतिक्रियाः राज्य सरकार ने 10 फरवरी, 2023 को वर्ष 2023–24 के लिए अपना बजट पेश किया। बजट की घोषणा के बाद, बार्क ट्रस्ट ने राज्य के बजट का विश्लेषण मीडिया, शोधकर्ताओं, नागरिकों, समाजिक संगठनों और विधायकों के साथ साझा किया। अखबारों में बजट पर लेख छपे और टीवी चैनलों पर विचार साझा किये गये। बार्क ने लेख और विश्लेषण सीएसओ और सोशल मीडिया के साथ साझा किया।

केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रियाः केंद्र सरकार ने 1 फरवरी, 2023 को वर्ष 2023–24 के लिए अपना बजट पेश किया। बार्क ने केंद्रीय बजट का विश्लेषण किया जो समाचार वेबसाइटों पर प्रकाशित हुआ।

राजस्थान सरकार द्वारा सीएसओ/एनजीओ के साथ आयोजित बजट घोषणा (2022–23) की स्थिति और समीक्षा पर बैठक (मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में) में भागीदारी की बार्क ट्रस्ट ने बजट घोषणा (2022–23) की स्थिति और समीक्षा पर सीएसओ/एनजीओ के लिए राजस्थान सरकार द्वारा (मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में) 1 अगस्त, 2022 को आयोजित बैठक में भाग लिया जिसमें प्रस्तावित कृषि क्षेत्र के लिए बजट घोषणा पर चर्चा की। 2022–23 के लिए चुनिंदा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों के लिए बजट घोषणाओं की स्थिति का विश्लेषण और समीक्षा करने के भी प्रयास किए गए हैं। वहीं पर खाद्य सुरक्षा, कृषि आदि की घोषणाओं के क्रियान्वयन पर भी सरकार के साथ अपने सुझाव साझा किये गये।
14 अप्रैल, 2023 को सीएसओ/एनजीओ के साथ राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित "बजट घोषणाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे" विषय पर इसी तरह की बैठक में भी बार्क ट्रस्ट ने भाग लिया।

एसटीडीएफ और एससीडीएफ अधिनियम, 2022 के नियम तैयार करने की मांगः

बार्क ट्रस्ट शुरुआत से ही राज्य में जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) और अनुसूचित जाति उपयोजना (एससी–एसपी जिसे पहले विशेष घटक योजना के रूप में जाना जाता था) के लिए कम आवंटन और कमजोर किर्यान्वयन का मुद्दा उठाता रहा है। बार्क–आस्था ने 2007 में इस

Budget 2023-24: Leaving the Marginalised Behind!

Nesar Ahmad | 02 Feb 2023

Economy India Politics SC/ST/OBC

The government's emphasis on inclusion in the budget 2023-24 has not been backed by the budgetary allocation for dalits, tribals, women and minorities.

Representational use only.Image Courtesy: Flickr

मुद्दे पर अपनी पहली रिपोर्ट प्रकाशित की थी। बार्क ने भी मीडिया और नीति निर्माताओं के साथ इस मुद्दे को उठाया है और राजस्थान में टीएसपी और एससी–एसपी के लिए कानून की लगातर बढ़ रही मांग में अपना योगदान दिया है।

अनु.जाति एवं अनुजनजाति आयोजना पर बार्क के प्रकाशन

BARC Publications onTSP and SC-SP

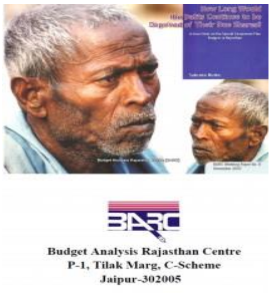

2007

2013

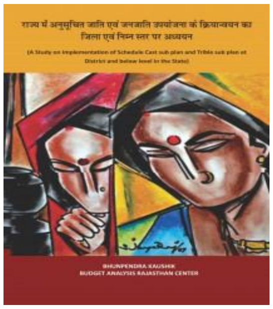

2015

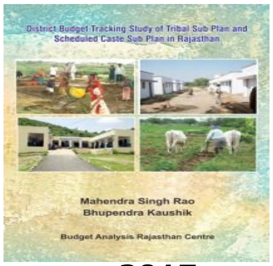

2017

2019

2020

2013 में राजस्थान की राज्य सरकार ने टीएसपी और एससी–एसपी पर एक विधेयक का मसौदा जारी किया था, लेकिन वह कानून नहीं बन सका। हाल के वर्षों में भी, राज्य सरकार ने बजट भाषण 2021–22 सहित विभिन्न अवसरों पर राजस्थान में टीएसपी और एससी–एसपी के लिए कानून लाने की अपनी मंशा की घोषणा करती रही है। राज्य सरकार एससी–एसटी कानून पर एक मसौदा लेकर आई थी जिसका नाम 'राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (वित्तीय संसाधनों की योजना, आवंटन और उपयोग) विधेयक 2022' था और इस पर सार्वजनिक टिप्पणियां भी आमंत्रित कीं। एक बार जब बिल सार्वजनिक रूपये उपलब्ध हो गया, तो ड्राफ्ट बिल पर अलग–अलग बैठकें आयोजित की गईं।

अंततः, राजस्थान सरकार ने उप–योजनाओं के उचित किर्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल 2022 में "राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (वित्तीय संसाधनों की योजना, आवंटन और उपयोग) अधिनियम, 2022" पारित किया। इसके बार बार्क अन्य सामाजिक संगठनों के साथ राज्य में "राजस्थान राज्य एसटीडीएफ और एससीडीएफ अधिनियम, 2022" के लिए नियम तैयार करने की मांग उठाता रहा। इस प्रक्रिया में बार्क ने सुचना एवं रोजगार अभियान और सेंटर फॉर दलित राइट्स के साथ अधिनियम के नियम तैयार

करने के लिए एक संवाद और अनौपचारिक चर्चा का आयोजन किया।

राजस्थान राज्य एसटीडीएफ एवं एससीडीएफ अधिनियम, 2022 पर परामर्शः
सेंटर फॉर दलित राइट्स (सीडीआर) ने बार्क ट्रस्ट, राजस्थान आदिवासी अधिकार मंच और अन्य के साथ मिलकर 29 जुलाई, 2022 को अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी, झालाना (जयपुर) में 'राजस्थान राज्य एसटीडीएफ और एससीडीएफ अधिनियम, 2022' पर एक दिवसीय परामर्श का आयोजन किया, जिसमें 40 से 50 लोग शामिल हुये थे।

स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम के लिए अभियानः

सत्तारूढ़ दल ने अपने घोषणापत्र में 'स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम' लाने का वादा किया था। जन स्वास्थ्य अभियान (जेएसए) के साथ बार्क ने राज्य में इस तरह के अधिनियम को पारित करने के लिए अभियान चलाया। यह मुद्दा बार्क ट्रस्ट द्वारा तैयार किए गए मांगों के चार्टर और सरकार द्वारा आयोजित बजट–पूर्व–परामर्श में भी उठाया गया था। इस पृष्ठभूमि में, राजस्थान सरकार ने 22 सितंबर, 2022 को 'राजस्थान स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार अधिनियम 2022' का मसौदा तैयार किया और सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय (जीओआर) की वेबसाइट पर मसौदा अपलोड किया। जन स्वास्थ्य अभियान द्वारा मसौदा विधेयक पर आयोजित विभिन्न बैठकों, चर्चाओं और परामर्शों में बार्क ट्रस्ट ने भाग लिया। और अंततः, 21 मार्च, 2023 को राज्य विधानसभा में "राजस्थान स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार अधिनियम, 2022" पारित हो गया।

राजस्थान स्वास्थ्य देखभाल अधिकार अधिनियम 2022 के मसौदे पर सुझाव प्रस्तुत करने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग (जीओआर) के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकः
प्रयास संस्थान और जेएसए के अन्य सदस्यों के साथ बार्क ट्रस्ट ने विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें कीं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (जीओआर) राजस्थान स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार (आर अधिनियम 2022) के मसौदे पर सुझाव देगा। 18 जनवरी, 2023 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (जीओआर) द्वारा बुलाई गई बैठक में बार्क ट्रस्ट ने भी भाग लिया।

राजस्थान स्वास्थ्य देखभाल अधिकार अधिनियम 2022 के मसौदे पर चर्चाः
जेएसए के बैनर के तले बार्क ट्रस्ट ने प्रयास संस्थान के साथ 'राजस्थान स्वास्थ्य देखभाल अधिकार अधिनियम 2022' के मसौदे पर चर्चा की। चर्चा में जन स्वास्थ्य अभियान (जेएसओ), और राज्य में स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठन/सीएसओ और पीओ के सदस्यों ने भाग लिया।

शोध अध्ययन

राजस्थान के 17 जिलों में जेंडर और जेंडर परिपेक्ष्य से जुड़ी लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं और अपेक्षाओं पर अध्ययनः

बार्क ट्रस्ट ने यूनिसेफ राजस्थान के सहयोग से राष्ट्रीय सेवा योजना (एनसीसी) के साथ मिलकर "राजस्थान के 17 जिलों में जेंडर और परिपेक्ष्य से जुड़ी लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं और अपेक्षाएं" पर एक शोध अध्ययन किया। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य कोविड के बाद की स्थिति में समाज और परिवार में पुरुषों और महिलाओं की भूमिका पर लोगों की समझ को जानजा थो। यह अध्ययन 17 जिलों में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित था। राज्य के अलवर, बाड़मेर, बीकानेर, भरतपुर, चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, दौसा, जालौर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, उदयपुर जिले इसमें शामिल थे।

अध्ययन के लिये आंकड़े 5322 उत्तरदाताओं से एकत्र किया गया था, जिसमें विभिन्न आयु–समूहों और सामाजिक समूहों के पुरुष और महिलाएं शामिल थे। 'राजस्थान में पोस्ट कोविड परिदृश्य में लड़कों और लड़कियों के जेंडर और भूमिका' की अवधारणा पर आधारित अध्ययन राजस्थान के 17 जिलों में आयोजित किया गया था, जिस के लिये 26 कॉलेजों के 170 एनएसएस छात्रों नं आंकड़े संग्रह किये।

अध्ययन के लिए डेटा संग्रह शुरू करने से पहले सभी 17 जिलों में सभी एनएसएस स्वयंसेवकों के लिए आमुखिकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। सभी आमुखिकरण कार्यक्रमों में आंकड़े संग्रह में भाग लेने वाले छात्रों से कहीं अधिक छात्र शामिल हुए। कुल मिलाकर 502 छात्र आमुखिकरण कार्यशालाओं में शामिल हुए। जिलेवार आमुखिकरण का विवरण नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है;

तालिकाः जिलेवार आमुखिकरण की तारीखें

जिला	**दिनांक**	**जिला**	**दिनांक**	**जिला**	**दिनांक**
जयपुर	26.ैमच.22	पाली	13.ब्बज.22	दौसा	01.छवअण.22
धौलपुर	1.ब्बज.22	उदयपुर	14.ब्बज.22	भरतपुर	15.छवअण.22
सवाई माधोपुर	7.ब्बज.22	डूंगरपुर	15.ब्बज.22	अलवर	28.ब्बजण.22
जोधपुर	10.ब्बज.22	चुरू	18.ब्बज.22	नागौर	03.छवअण.22
बाड़मेर	11.ब्बज.22	श्रीगंगानगर	19.ब्बज.22	बीकानेर	04.छवअण.22
जालौर	12.ब्बज.22	कोटा	17.ब्बज.22	दौसा	

अनुभव साझा करने की कार्यशालाएँ राज्य के 6 महाविद्यालयों में "एनएसएस स्वयंसेवकों के साथ ओपन फोरम" शीर्षक के साथ आयोजित की गईं। बार्क ट्रस्ट ने 27 दिसंबर, 2022 को होटल रमाडा (जयपुर) में कोविड–19 में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं और अपेक्षाओं के बारे में लैंगिक धारणाओं पर प्रारंभिक निष्कर्षों को साझा करने के लिए एक संवाद भी आयोजित किया।

राजस्थान में युवाओं के बीच लैंगिक संवेदनशीलताः आरंभिक मूल्यांकनः

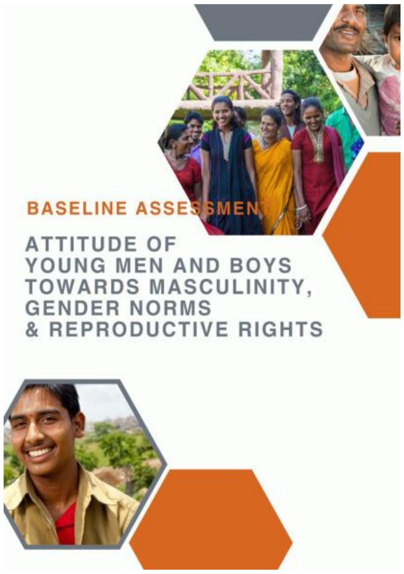

बार्क ट्रस्ट ने यूएनएफपीए के सहयोग से सीकोडिकोन द्वारा शुरू किए गए "राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में युवाओं के बीच लैंगिक संवेदनशीलताः बेसलाइन मूल्यांकन" पर अध्ययन किया। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, पुरुषत्व और जेंडर आधारित हिंसा जैसे जेंडर संबंधी मुद्दों के प्रति पुरुषों के ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहारों (केएपी) को समझना था। नमूना अध्ययन के लिये पूरूषों को सवाईमाधोपूर जिले की 33 पंचायतों में सीकोडिकोन द्वारा गठित युवा समूहों में के कुल 154 युवाओं/पुरुषों का चयन किया गया था।

युवाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों का संकलनः

बार्क ट्रस्ट ने यूएनएफपीए के समर्थन से सीनडिकोन द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम "राजस्थान में युवाओं के लिए सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की संकलन" तैयारी किया और युवाओं के लिए सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की मैपिंग पर आधारित एक पुस्तिका तैयार की गई। पुस्तिका में युवाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास और रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, खेल आदि से संबंधित सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का विवरण दिया गया है।

राजस्थान में युवाओं पर स्थिति रिपोर्टः

बार्क ट्रस्ट ने यूएनएफपीए के समर्थन से सीनडिकोन द्वारा शुरू की गई राजस्थान में युवाओं पर स्थिति रिपोर्ट भी तैयार की। यह स्थिति रिपोर्ट में राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक मुद्दों और सामाजिक–आर्थिक संकेतकों के संबंध में युवाओं की स्थिति के विभिन्न संकेतकों पर प्रकाश डालती है।

राज्य की जलवायु परिवर्तन नीति पर सरकार की टिप्पणियाँः

राजस्थान की राज्य सरकार ने राज्य की जलवायु परिवर्तन पर नीति का मसौदा तैयार किया और इसे सुझाव व टिप्पणियों के लिए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय (जीओआर) की वेबसाइट पर अपलोड किया। बार्क ट्रस्ट ने राजस्थान की जलवायु परिवर्तन नीति (2022) के मसौदे पर टिप्पणियों और सुझावों के लिए एक नोट तैयार किया और इसे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय को भेजा।

सम्मेलन और कार्यशालाएँ

वर्ष 2022–23 के दौरान निम्नलिखित सम्मेलन और कार्यशालाएँ आयोजित की गईः

जेंडर की धारणा के अध्ययन के तहत ओरिएंटेशन और कार्यशालाएँ

- **राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों की आमुखीकरण कार्यशालाएंः** बार्क ट्रस्ट और यूनिसेफ ने राष्ट्रीय सेवा योजना के सहयोग से "राजस्थान में पोस्ट कोविड–19 परिदृश्य में लड़कों और लड़कियों के जेंडर और भूमिकाएं" विषय पर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों का आमुखीकरण आयोजित किया, जो राजस्थान के 17 जिलों के महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया।
- **राजस्थान में कोविड–19 के बाद के परिदृश्य में जेंडर की धारणा पर छात्रों के साथ संवाद और 6 कॉलेजों में राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों के साथ जुड़ावः**
- **राजस्थान में कोविड–19 के बाद के परिदृश्य में जेंडर की धारणा पर राज्य स्तरीय संवाद और राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों के साथ जुड़ावः** जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बार्क ट्रस्ट ने जेंडर की धारणाओं पर हुए अध्ययन के प्रारंभिक निष्कर्षों को साझा करने के लिए 27 दिसंबर, 2022 को होटल रमाडा (जयपुर) में इस संवाद का आयोजन किया जिसका विषय था – कोविड–19 में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाएँ और अपेक्षाएँ और आगे का रास्ता।

कृषि बजट एवं नीति पर कार्यशाला एवं परामर्शः
बार्क और सीबीजीए मिलकर एक राज्य स्तरीय परामर्श बैठक और 3 जिला स्तरीय परामर्श बैठक आयोजित किए। राज्य स्तरीय परामर्श जयपुर में तथा जिला परामर्श उदयपुर, अलवर एवं बाडमेर जिलों में आयोजित किया गया।

"राजस्थान में समावेशी और सहज न्यूनतम–कार्बन विकास की ओर" पर गोलमेजः बार्क ट्रस्ट, सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी (सीबीजीए), नई दिल्ली और बास्क रिसर्च फाउंडेशन ने साथ मिलकर "समावेशी और सहज से न्यूनतम–कार्बन विकास की ओर" विषय पर एक दिवसीय गोलमेज का आयोजन हिल्टन होटल, जयपुर में किया। इसमें राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड से श्री नवीन शर्मा (विशेष कर्तव्य अधिकारी), बागवानी विभाग से श्री दानवीर वर्मा (उप निदेशक), सीईडीएस से प्रोफेसर एम.एस. राठौड़ (निदेशक) और सरकार के संबंधित विभागों, गैर सरकारी संगठनों/सीएसओ, शैक्षणिक और विकास संगठनों के 30 से अधिक लोगों ने भाग लिया।

सहयोग और नेटवर्किंग

बार्क ट्रस्ट ने हमेशा विभिन्न राष्ट्र और राज्य स्तरीय नेटवर्क और जैसे कि फैमिनिस्ट पॉलिसी कलेक्टिव, पीपुल्स बजट इनिशिएटिव, रोज़ी रोटी अधिकार अभिमान, सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान, राजस्थान आदिवासी अधिकार मंच आदि संगठनों के साथ मिलकर काम किया है। बार्क के बजट–पूर्व परामर्श और अन्य कार्यक्रमों में राज्य के गैर–सरकारी संगठनों काफी संख्या में प्रतिभागी भाग लेते है। वर्ष 2022–23 के दौरान, जैसा कि ऊपर बताया गया है, बार्क ने विभिन्न शोध अध्ययन और हस्तक्षेप आयोजित करने के लिए कई संगठनों के साथ सहयोग किया। इसके अलावा, बार्क ट्रस्ट ने विभिन्न संगठनों द्वारा की गई विभिन्न बैठकों, सेमिनारों और एडवोकेसी पहलों में भी भाग लिया।

दलित अधिकार केंद्र (सीडीआर) और सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान (एसआर अभियान): बार्क ट्रस्ट ने ''राजस्थान अनुसूचित जाति विकास निधि और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (वित्तीय संसाधनों की योजना, आवंटन और उपयोग) अधिनियम, 2022" पर दलित अधिकार केंद्र, सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान, राजस्थान आदिवासी अधिकार मंच और आस्था के साथ अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी, झालाना (जयपुर) में एक दिवसीय परामर्श आयोजित करने में सहयोग किया जिसमें 40 से 50 प्रतिभागी शामिल रहे।

फेमिनिस्ट पॉलिसी कलेक्टिवः बार्क ट्रस्ट ने केंद्रीय बजट 2023–24 के लिए बजट–पूर्व–परामर्श के आयोजन में फेमिनिस्ट पॉलिसी कलेक्टिव के साथ सहयोग किया।

सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी (सीबीजीए): बार्क ट्रस्ट ने सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी (सीबीजीए) के साथ सहयोग किया, और कृषि नीति, महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले किसानों के विभिन्न मुद्दों, राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना और जलवायु परिवर्तन नीति पर बैठकें आयोजित कीं।

इंटर्न्स

इस वर्ष बार्क ट्रस्ट में सोफिया कॉलेज, अजमेर (राजस्थान), अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (बेंगलुरु) और राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़ (राजस्थान) से इंटर्न आए। इन प्रशिक्षुओं ने विभिन्न विषयों पर काम किया, जैसे – महिला और जेंडर बजटिंग, कृषि नीतियां, राजस्थान में शिक्षा की स्थिति, सतत विकास लक्ष्य–एसडीजी और एसडीजी प्राप्त करने में राजस्थान की स्थिति। इसके अलावा प्रशिक्षु "राजस्थान के 17 जिलों में जेंडर और परिपेक्ष्य के परिदृश्य में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं और अपेक्षाओं" और "राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में युवाओं के बीच जेंडर संवेदनशीलताः आधारभूत मूल्यांकन" पर आयोजित विभिन्न शोध अध्ययनों में भी शामिल थे।

बार्क संसाधन केंद्र के रूप में

जैसा कि पहले कहा गया है, बार्क ट्रस्ट की भूमिकाओं में से एक गैर सरकारी संस्थाओं के साथ–साथ पत्रकारों, विधायकों और बड़े पैमाने पर जनता के लिए बजअ एवं नीतियों पर एक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना भी हैं। सरकार के साथ नीतियों को मज़बूत करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान डेटा और विश्लेषण प्रदान करने के लिए केंद्र की स्थापना की गई थी। वर्ष 2022–23 के दौरान भी बार्क ने विभिन्न संगठनों को सहायता प्रदान की।

समाचार पत्रों सहित विभिन्न समाचार लेखों ने अपनी रिपोर्टों में राज्य के बजट पर बार्क के विश्लेषण का हवाला दिया गया। बार्क सदस्यों ने समाचार पत्रों और समाचार पोर्टलों में भी अपने लेख प्रकाशित किए।

ऑनलाइन समाचार पोर्टलों पर प्रकाशित लेख

- घोषणाओं का क्रियांवयन बड़ी चुनौती (हिन्दी): पंजाब केसरी, जयपुर में।
- बजट 2023–24: लिविंग द मार्जिनलाइज्ड बिहाइंड।

(ीजजचेरूध्धूण्दमूबसपबाण्पदध्ठनकहमज.2023.24.स्मंअपदह.डंतहपदंसपेमक.ठमीपदक)

- राजस्थान बजट 2023–24: अनाउंसमेंट, यूजफुल एंड अपलेंटी, विल देयर बी इफेक्टिव इम्पलिमेंटेशन।

(ीजजचेरूध्धूण्दमूबसपबाण्पदध्ठनकहमज.2023.24.स्मंअपदह.डंतहपदंसपेमक.ठमीपदक)

प्रकाशनः

राजस्थान में एसडीजी और हाशिए पर रहने वाले समूहों पर श्रृंखलाः बार्क ट्रस्ट ने राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों और हाशिए पर रहने वाले समूहों पर नीति प्रपत्र की एक श्रृंखला प्रकाशित करने की शुरुआत की। वर्ष 2022–23 में श्रृंखला के तहत "राजस्थान में एसडीजी और अल्पसंख्यकः नीतियां, बजट और कार्यक्रम

2022–23 में लाए गए अन्य प्रकाशनों में शामिल हैं:

1. "राजस्थान में बच्चों, किशोरों और युवाओं के लिए सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम" पर एक पुस्तिका (हिंदी में)

बार्क ट्रस्ट के सभी प्रकाशन बार्क ट्रस्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सांगठनिक विकास

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर आंतरिक शिकायत समिति की बैठक और साथ में प्रशिक्षण

बार्क ट्रस्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत अनिवार्य यौन उत्पीड़न पर एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। 3 अक्टूबर, 2022 को पहला यौन शोषण और दुर्व्यवहार रोकथाम (पीएसइए) प्रशिक्षण बार्क टीम के सदस्यों के लिए सत्र आयोजित किया गया, जिसमें यौन उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव, यौन उत्पीड़न के आयाम, रूप और विशाखा दिशानिर्देशों सहित लैंगिक मुद्दों को समझने पर जोर दिया गया। दूसरा प्रशिक्षण 18 मार्च, 2023 को बार्क टीम के सदस्यों के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए बार्क ट्रस्ट की नीति पर आयोजित किया गया था।

वेबसाइट

बार्क ट्रस्ट की वेबसाइट (ण्इंतबजतनेजण्वतह) नागरिकों और अन्य संगठनों को राजस्थान राज्य के बजट और सार्वजनिक नीतियों के बारे में गरीब–समर्थक और हाशिए पर रहने वाले लोगों के दृ ष्टिकोण के साथ जानकारी प्राप्त करने में मदद करने के लिए बनाई गई है। बजट और नीति संबंधी जानकारी के लिए एक पोर्टल के रूप में यह साइट राजस्थान की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अवलोकन प्रस्तुत करती है, और राज्य के पिछले कुछ वर्षों के बजट और नीतियों की एक सरल रूप में रखने का प्रयास करती है।

वेबसाइट हमारे रणनीतिक फोकस को प्रतिबिंबित करने के लिए संरचित है। इसके "हमारे बारे में", जो आगंतुकों को ट्रस्ट के विजन, मिशन और उद्देश्यों से परिचित कराता है, साइट में के अलावा, "राजस्थान बजट आंकड़े सरलीकृत" का अनुभाग हैं, जो राजस्थान सरकार के बजट डेटा को सरल रूप में प्रस्तुत करता है "पंचायत बजट" अनुभाग में आगंतुकों को पंचायतों के साथ ट्रस्ट के कार्यों से परिचित कराया गया है। "राजस्थान में पोषण" अनुभाग राज्य में पोषण की अद्यतन स्थिति प्रदान करता है, जबकि प्रकाशन अनुभाग हमारे सभी प्रकाशनों की ऑनलाइन उपलब्ध करता है।

'राजस्थान का बजट सरलीकृत' अनुभाग में राज्य के बजट को क्षेत्रवार और विभिन्न प्रमुखों, विभागवार बजट, योजनावार बजट और स्वास्थ्य और पोषण के लिए बजट के साथ–साथ टीएसपी और एससी–एसपी बजट, जेंडर बजट, बच्चों के लिए बजट और एसडीजी के लिए बजट आदि के संकलन पर विभिन्न डेटा शीट हैं।

और अंत में

बार्क ट्रस्ट ने वर्ष 2022–23 के दौरान भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपना प्रयास जारी रखा है। राज्य सरकार ने दलितों और आदिवासियों के लिए बजट आवंटन को कानूनी समर्थन देते हुए "राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (वित्तीय संसाधनों की योजना, आवंटन और उपयोग) अधिनियम (2022) पारित किया। इसी प्रकार, राज्य सरकार ने 21 मार्च, 2023 को राज्य विधानसभा में "राजस्थान स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार अधिनियम, 2022" पारित किया। राजस्थान सरकार द्वारा पारित ये दोनों अधिनियम बार्क ट्रस्ट के लिए संतुष्टि का विषय हैं क्योंकि बार्क इस तरह कानूनों की मांग करता रहा है। सतत् विकास लक्ष्य और हाशिये के लोगों पर श्रृंखला का प्रकाशन भी सही दिशा में महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इससे असमानता और हाशिए के समुदायों के मुद्दों को बहस में लाने में मदद मिलेगी।

बार्क ट्रस्ट नीति, बजट और शासन परिदृश्य में वंचित लोगों के मुद्दों को उजागर करने के अपने प्रयास जारी रखेगा।

परिशिष्ट

परिशिष्ट – 1

2022–23 में बार्क ट्रस्ट टीम के सदस्यों ने कार्यशालाओं और सेमिनारों में भाग लियाः

नेसार अहमद, निदेशक

नीचे सूचीबद्ध विभिन्न कार्यक्रमों में वक्ता/संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लियाः

- 9 अगस्त 2022 को सीकोडिकोन, जयपुर द्वारा आयोजित "जलवायु परिवर्तन" पर परामर्श में भाग लिया।
- 16 सितंबर, 2022 को महिला एवं बाल विकास निगम (बिहार सरकार) और सी3 इंडिया द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए आयोजित "जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग (जीआरबी)" प्रशिक्षण में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया।
- 29 अगस्त, 2022 को खान श्रमिक सुरक्षा अभियान (एमएलपीसी), द्वारा आयोजित जयपुर में "जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) और खान श्रमिक बोर्ड" बैठक में भाग लिया।
- 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2022 तक जयपुर (राजस्थान) में यूनिसेफ द्वारा आयोजित "परिणाम आधारित प्रबंधन (आरबीएम)" कार्यशाला में भाग लिया।
- 18–19 नवंबर, 2022 को जयपुर में विकास संवाद द्वारा "एनजीओ के लिए संचार" विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया।
- 1–2 दिसंबर, 2022 को दिल्ली में ''संयुक्त राष्ट्र–महिला'' (न्छूवउमद) द्वारा आयोजित "जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग (जीआरबी)" पर प्रशिक्षण में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया।
- 14–15 दिसंबर, 2022 को नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया (एनएफआई), नई दिल्ली द्वारा आयोजित "एनएफआई सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम" पर कार्यशाला में भाग लिया।
- 4 जनवरी 2023 को प्रयास, चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा आयोजित "एनीमिया, मातृ मृत्युदर एवं जीवन का अधिकार" विषय पर बैठक में भाग लिया।
- 11 फरवरी 2023 को जयपुर में सेफटिपिन द्वारा आयोजित "शहरी विकास एवं महिला

सुरक्षा" विषय पर कार्यशाला में रिसोर्स पर्सन के रूप में भाग लिया।

- 21 फरवरी, 2023 को दिल्ली में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (भारत सरकार) और यूएनवुमेन द्वारा आयोजित "जेण्डर बजट वक्तव्य स्टेटमेंट पर राष्ट्रीय हितधारक परामर्श" में भाग लिया।
- 25 फरवरी, 2023 को जयपुर में आईआईआईएम द्वारा आयोजित "केंद्रीय बजट पर चर्चाः 2023–24" में वक्ता के रूप में भाग लिया।
- 11 फरवरी 2023 को जयपुर में सेफ्टीपिन द्वारा आयोजित "शहरी विकास एवं महिला सुरक्षा" कार्यशाला में रिसोर्स पर्सन के रूप में भाग लिया।
- 25–27 फरवरी, 2023 को सामाजिक विकास परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यशाला "विस्थापित लोगों के पुनर्वास और पुनर्वास के लिए क्षमता निर्माण'' में भाग लिया।
- 23–26 मार्च, 2023 को जयपुर में आस्था द्वारा आयोजित "चलो बजट देखना सीखें'' (आइए बजट देखना सीखें) पर प्रशिक्षण कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया।

रिसोर्स पर्सन – संदर्भ व्यक्ति

परिशिष्ट – 2
बार्क ट्रस्ट के ट्रस्टी

डॉ. वर्जीनिया (जिनी) श्रीवास्तव, अध्यक्ष

डॉ. जिनी श्रीवास्तव आस्था संस्थान के संस्थापकों में से हैं और उन्होंने एकल नारी शक्ति संगठन और बार्क ट्रस्ट जैसे विभिन्न संगठनों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह 1970 से राजस्थान में महिलाओं, आदिवासियों और समाज के अन्य उत्पीड़ित वर्गों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर काम कर रही हैं। उन्होंने 1970 में टोरंटो विश्वविद्यालय, कनाडा से वयस्क शिक्षा में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। 1980 में डॉ. जिनी श्रीवास्तव की डॉक्टरेट पूरी की जिसकी थीसिस "भारत में महिलाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम" पर थी।

डॉ. प्रदीप भार्गव, सचिव

हाल ही में सेवानिवृत्त हुए डॉ. प्रदीप भार्गव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (एमपी) में प्रोफेसर रहे हैं। इससे पहले, वह 1987 से 2007 तक इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, जयपुर और जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद में भी संकाय सदस्य रहे हैं। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। उनके लेख विभिन्न भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकारों और बहु–पक्षीय एजेंसियों के साथ कई नीतिगत संवादों का नेतृत्व किया है।

सुश्री शारदा जैन, कोषाध्यक्ष

सुश्री शारदा जैन ने 30 से अधिक वर्षों तक आस्था संस्थान में लेखा और वित्त समन्वयक के रूप में काम किया है। उन्होंने आस्था की समग्र वित्तीय गतिविधियों का नेतृत्व किया है और संगठन का वार्षिक बजट, डोनर एजेंसियों के लिए खाते और वित्तीय रिपोर्ट, टैक्स अनुपालन, संगठन की लेखांकन और लेखा जांच आवश्यकताओं को तैयार करने का व्यापक अनुभव है।

सुश्री अदिति मेहता, आईएएस (सेवानिवृत्त)

सुश्री अदिति मेहता भारतीय प्रशासनिक सेवा की सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं। उन्होंने हार्वर्ड

विश्वविद्यालय से एम.ए. (अर्थशास्त्र) और एमबीए (प्रशासन) किया हैं। आईएएस के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने राजस्थान सरकार में प्रशासन, वित्त और सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और राजस्थान सरकार से अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुईं।

डॉ. पवित्र मोहन

डॉ. पवित्र मोहन एक बाल रोग विशेषज्ञ और सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सक हैं, और उन्होंने राजस्थान राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य पहल को बढ़ाने में योगदान दिया है। उन्होंने पहले यूनिसेफ इंडिया के कंट्री ऑफिस में वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया है। वह अशोका फेलो और नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम के फेलो हैं। वह बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के न्यासी बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

डॉ. नेसार अहमद, निदेशक (पदेन सदस्य, बीओटी)

नेसार अहमद बार्क ट्रस्ट के संस्थापक निदेशक हैं। उन्होंने "खनन क्षेत्र में महिला और प्रौद्योगिकी" से संबंधित विषय पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से पीएच.डी. की है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर किया है और उन्हें भारत में विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों के साथ काम करने का अनुभव है। उनकी रुचि के क्षेत्रों में गरीबी, आजीविका, खाद्य सुरक्षा, विकास–प्रेरित विस्थापन, जेंडर, महिलाओं के अधिकार, बाल अधिकार और शासन के मुद्दे, विकेंद्रीकरण और बजट विश्लेषण आदि शामिल हैं।

परिशिष्ट– 3
2022–23 के दौरान बार्क ट्रस्ट की आय और व्यय का विवरण

BUDGET ANALYSIS AND RESEARCH CENTRE TRUST

Registered Office - 1/244, SFS, Agarwal Farm, Mansarovar, Jaipur - 302020

Income & Expenditure for the year ended 31st March 2023

	Schedule		Amount
Income:			
Unutilised Grant b/f			-
Grant & Consultancy Received			
Consultation fees recd. from CECOEDECON			1,149,500.00
Unicef - Promoting CAB and Covid-19 Vaccines			2,431,500.00
Other Incomes			
Bank Interest - FDR			3,057.00
Bank Interest - Saving Account			21,243.00
Interest on IT Refund (A.Y. 2021-22)			1,489.00
		'a'	3,606,789.00
Expenditures :			
Project Expenditures			
Unicef - Promoting CAB and Covid-19 Vaccines			2,431,500.00
Consultancy			17,000.00
Youth Study and Baseline Assessment for CECOEDECON			337,453.00
Administration Expenses	"F"		128,773.34
Capital Expenditure	"C"		25,054.00
		'b'	2,939,780.34
Excess of income over expenditure			667,008.66
Balance carried to Balance Sheet		(a-b-c)	667,008.66

Significant Accounting Policies & Notes to Accounts are attached

The schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements.

In Terms of our Audit Report even date attached

For D Bohra & Associates

Chartered Accountants

FRN - 015231C

D Bohra & Associates CA FRN-015231C M. No.: 408218 Chartered Accountants

(CA. Dinesh Kumar Bohra)

Proprietor

M.No. - 408218

Place : Jaipur

Date : 31-08-2023

For Budget Analysis and Research Centre Trust

(Sharda Jain)

Treasurer

TREASURER

Budget Analysis and Research Centre Trust

(Nesar Ahmad)

Director

DIRECTOR

Budget Analysis and Research Centre Trust

परिशिष्ट– 4

बार्क ट्रस्ट के प्रकाशनों की सूची

मुख्य पृष्ठ	शीर्षक	विवरण
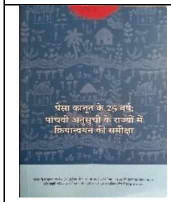	"पेसा के 25 वर्षः राजस्थान में धीमी प्रगति"	यह अध्ययन राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन को पूरा करता है।
	"राजस्थान में बच्चों, किशोरों और युवाओं के लिए सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम" (हिंदी में)	पुस्तिका में राजस्थान में बच्चों, किशोरों और युवाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों का विवरण दिया गया है
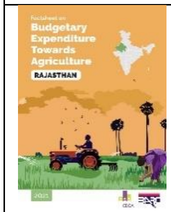	राजस्थान में कृषि के लिए बजट पर फैक्टशीट	राजस्थान में कृषि के प्रति बजटीय व्यय पर सीबीजीए के साथ फैक्टशीट
	राजस्थान में कृषि पर एक संक्षिप्त नीति प्रपत्र	राजस्थान में कृषिः स्थिति, नीतियां और बजट (हिन्दी में), सीबीजीए और आस्था के साथ
	राजस्थान बजट नोट 2021	राज्य बजट 2021–22 पर एक नोट
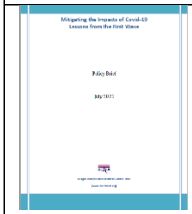	कोविड–19 के प्रभावों को कम करना –पहली लहर से सीख नीति संक्षिप्त (2021)	कोविड–19 के प्रभाव पर एक नीति सार–संक्षिप्त
	कोविड–19ः राजस्थान और केंद्र सरकार द्वारा घोषित राहत उपाय– 2 (2021)	राजस्थान और केंद्र सरकार द्वारा राहत उपायों की घोषणा

	कोविड–19: राजस्थान और केंद्र सरकार द्वारा घोषित राहत उपाय (2021)	राजस्थान और केंद्र सरकार द्वारा राहत उपायों की घोषणा
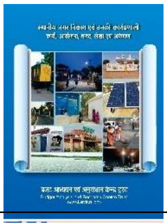	शहरी शासन पर मैनुअल (हिन्दी) (2021)	राजस्थान में शहरी स्थानीय निकायों के कामकाज, योजना, बजट और खातों पर एक मैनुअल
	अल्पसंख्यकों के लिए बजट और कार्यक्रमों पर नीति संक्षिप्त प्रपत्र– (हिन्दी) (2021)	प्रमुख मुद्दा राजस्थान में अल्प संख्यकों का
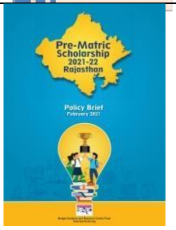	राजस्थान में प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति 2021–22 पर नीति संक्षिप्त अध्ययन रिपोर्ट: (2021)	प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति में संसाधन अंतर का अनुमान
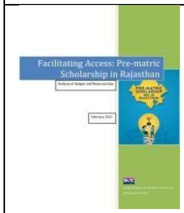	प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति (2021) में संसाधन अंतर	प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति में संसाधन अंतर का अनुमान
	कोविड–19: राजस्थान और केंद्र सरकार द्वारा घोषित राहत उपाय (2020)	राजस्थान और केंद्र सरकार द्वारा राहत उपायों की घोषणा
	राजस्थान में टीएसपी और एससीएसपी पर नीति संक्षिप्त (हिंदी) (2019)	राजस्थान में टीएसपी और एससी–एसपी के लिए कानून पर बहस करते हुए एक नीति संक्षिप्त विवरण
	पोषण में संसाधन अंतर पर नीति संक्षिप्त – राजस्थान (2019)	राजस्थान में पोषण योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन हेतु आवश्यक बजट का अनुमान

	पोषण में संसाधन अंतर पर नीति संक्षिप्त– धौलपुर (2019)	धौलपुर जिले में पोषण योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन हेतु आवश्यक बजट का अनुमान
	पोषण में संसाधन अंतर पर नीति संक्षिप्त – उदयपुर (2019)	उदयपुर जिले में पोषण योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन हेतु आवश्यक बजट का अनुमान
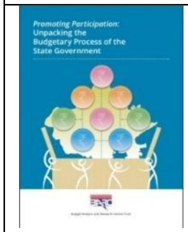	भागीदारी को बढ़ावा देनाः राज्य सरकार की बजटीय प्रक्रिया को जन के लिए खोलना (2019)	राज्य में नागरिक समाज एवं जन संगठनों एवं आम लोगों के लिए बजट चक्र एवं बजटीय प्रक्रिया को समझाना
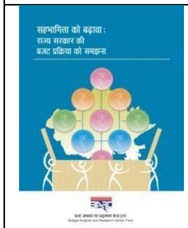	भागीदारी को बढ़ावा देनाः राज्य सरकार की बजटीय प्रक्रिया को जन के लिए खोलना (हिंदी) (2019)	राज्य में नागरिक समाज एवं जन संगठनों एवं आम लोगों के लिए बजट चक्र एवं बजटीय प्रक्रिया को समझाना
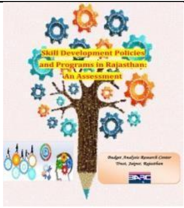	राजस्थान में कौशल विकास नीतियां और कार्यक्रमः एक सिंहावलोकन (2019)	राजस्थान में कौशल विकास नीतियों एवं कार्यक्रमों का विश्लेषण
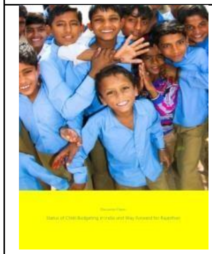	भारत में बाल बजट की स्थिति और राजस्थान के लिए आगे की राह (2019)	भारत में बाल बजट की स्थिति और राजस्थान कैसे आगे बढ़ सकता है।

	जिला खनिज निधि ट्रस्ट पर नीति संक्षिप्त (हिन्दी) (2019)	राजस्थान में डीएमएफटी निधि के उपयोग पर एक नीति संक्षिप्त विवरण
	राजस्थान में सामाजिक क्षेत्र का बजट (2019)	पिछले पांच वर्षों में राजस्थान में सामाजिक क्षेत्र के बजट का विश्लेषण
	ग्राम कार्य दिशानिर्देश (ग्राम कार्य निर्देशिका (जीकेएन)) (हिंदी) (2017)	ग्राम ग्राम कार्य दिशानिर्देश (ग्राम कार्य निर्देशिका (जीकेएन)) एक विस्तृत दिशानिर्देश है जो पंचायतों के लिए अपना काम करने के लिए मानदंड निर्धारित करता है। यह मैनुअल सरल हिंदी में जीकेएन का सारांश प्रदान करता है।
	उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था (हिन्दी) (2016)	यह पुस्तिका उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था का सारांश देती है और उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम पर आधारित है।
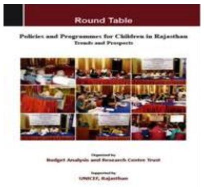	राजस्थान में बच्चों के लिए नीतियां और कार्यक्रम (2016)	यह पुस्तिका राजस्थान में बच्चों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर प्रकाश डालती है और इसे यूनिसेफ, राजस्थान के सहयोग से प्रकाशित किया गया है।
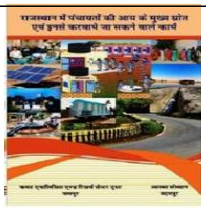	पंचायतों के लिए निधि के स्रोत (2016) (हिन्दी में)	यह पुस्तिका राजस्थान में पंचायतों को उपलब्ध धन के स्रोतों और उनके दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध धन से क्या कार्य किए जा सकते हैं, इस पर प्रकाश डालती है।

परिशिष्ट 5

2022—23 में मीडिया में बार्क

लैंगिक भूमिकाओं के सर्वे को लेव
यूनिसेफ का प्रशिक्षण आयोजित

उदयपुर। भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय में यूनिसेफ और बजट एनालिसिस रिसर्च सेंटर जयपुर की ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को लैंगिक समानता और लैंगिक भूमिकाओं पर सर्वे को लेकर आमुखीकरण शिविर और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलसचिव परबत सिंह राठौड़ ने कहा कि वर्तमान में लैंगिक समानता की प्रबल आवश्यकता है आज के युग में हमें रूढ़िवादी सोच से बाहर आकर हमें पुरुष और महिला की भूमिकाओं पर सोचना होगा और बिना पूर्वाग्रह के सभी को अब समान अवसर मिलने चाहिए। यूनिसेफ के स्टेट कंसलटेंट जमीर अनवर ने बताया कि लैंगिक समानता पर राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को 4 आयु वर्ग 11 से 14 वर्ष 15 से 19 वर्ष 19 से 35 वर्ष और 35 से ऊपर आयु वर्ग के 304 व्यक्तियों को 1 सप्ताह में गूगल फॉर्म के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में घर-घर जाकर सर्वे करना है जिसमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर बराबर होगी और लैंगिक मुद्दों पर उनकी राय जाननी है।

बीएन विश्वविद्यालय के एनएसएस विश्वविद्यालय समन्वयक डॉ. ज्योतिरादित्य सिंह भाटी ने बताया कि सर्वे में वॉलिंटियर्स शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लैंगिक मुद्दों पर पर जानने की और जन जागरूकता लाने का प्रयास करेंगे। यह सर्वे राजस्थान के 17 जिलों में किया जा रहा है जिसमें उदयपुर जिला भी शामिल है। उदयपुर में भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय के 12 वॉलिंटियर्स का

चयन इस सर्वे के लिए किय
जिसकी मॉनिटरिंग विश्वविद्य
प्रोग्राम ऑफिसर करेंगे।
अधिकारी डॉ. गिरधरपाल
बताया कि शिविर में वॉलि
लैंगिक मुद्दों पर अपनी जिज्ञास
संदर्भ व्यक्तियों से चर्चा
संदर्भ व्यक्तियों द्वारा आगामी
होने वाले सर्वे के प्रत्येक
विस्तृत चर्चा की गई। कार्य
प्रारंभ में अतिथियों का
कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सृष्टि
चुंडावत ने किया। यह
विश्वविद्यालय के
अधिकारी डॉ. कमल सिंह
दी।

उदयपुर रविवार दिनांक 16 अक्टूबर 202

अलवर. कला कॉलेज में लैंगिक समानता विषय पर आमुखीकरण व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया ग

लैंगिक समानता विषय पर हुआ आमुखीकरण व प्रशिक्षण कार्यक्रम

अलवर| बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में शुक्रवार को राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना के पुरस्कार से सम्मानित डॉ. सरोज मीना के निर्देशन में लैंगिक समानता विषय पर बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र ट्रस्ट द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से आमुखिकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र ट्रस्ट की ओर से शकील खान बजट एनालिस्ट एवं नीरज महला ने संबोधित किया। शकील खान ने बताया कि लैंगिक समानता समाज के लिए जरूरी है। इसमें असमानता होने पर पुरूष और महिलाओं की भूमिका में बदलाव आ जाता है जो न केवल समाज के लिए बल्कि देश के लिए भी घातक मानी जाती है। समाज में पूर्वाग्रह के कारण पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति दयनीय हो जाती है। राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रभारी डॉ सरोज मीना ने बताया कि महिलाओं को पुरुष प्रधान समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अग्रणी भूमिका निर्वाह करनी होगी ताकि समाज में पूर्वाग्रहों को मिटाया जा सके। जिससे वर्तमान में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिल सके और महिलाओं को पुरूषों के समान सभी तरह अधिकार मिल सके। प्राचार्य डॉ लवलीना व्यास ने बताया कि किस प्रकार से लैंगिक

असमानता आज भी
अपना वर्चस्व क़ायम कि
इस अवसर पर महावि
वरिष्ठ संकाय सदस्य
प्रताप जाजोरिया, डॉ
उपस्थित रहे। स्वयं
संगीता सैनी, खुशी, से
चौधरी, गौरव आदि
स्वयंसेवक उपस्थित रहे
वाणिज्य महाविद्यालय
राष्ट्रीय सेवा योजना
अधिकारी डॉ भगवान
लोकेश, कीर्ति, हर्षि
जिगर शर्मा चयनित
की टीम के साथ उ
कार्यक्रम के अन्त
सहाय मीणा के द्वारा
टीम का धन्यवाद
गया।

समाज को भेदभाव से मुक्त करने की जरूरत

नवज्योति/कोटा। राजकीय महाविद्यालय कोटा व गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई बार्क व यूनिसेफ की ओर से सोमवार को रामानुजन सभागार में ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्य अतिथि जयपुर से आए बार्क निदेशक निसार अहमद ने लैंगिक समानता की जानकारी देते हुए कहा, लिंग आधारित भेदभाव से समाज को मुक्त करने की जरूरत है। पोक्सो एक्ट कानूनी प्रावधानों व अधिकारों की जानकारी दी। विशिष्ट अतिथि कॉलेज शिक्षा के सहायक निदेशक डॉ. रघुराज सिंह परिहार ने कहा, आज हम 21वीं सदी में रहते हैं फिर भी लैंगिक समानता विद्यमान होना चिंता का विषय है। इस बुराई को दूर करने की जिम्मेदारी युवाओं की है। डॉ. विवेक मिश्र ने युवाओं को एनएसएस संगठन का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि समाज व राष्ट्र के विकास के लिए मंच प्रदान करने वाला यह महत्वपूर्ण संगठन है। कार्यक्रम अधिकारी डॉ. राम लक्ष्मण सैनी ने संचालन किया। अध्यक्षता गवर्नमेंट कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. लालचंद कहार ने की। डॉ. समय सिंह मीना ने बताया कि कार्यक्रम में 35 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया। जिनमें से 13 स्वयंसेवकों को लैंगिक सर्वे के लिए चयनित किया।

लैंगिक भूमिकाओं के सर्वे को लेव यूनिसेफ का प्रशिक्षण आयोजित

उदयपुर। भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय में यूनिसेफ और बजट एनालिसिस रिसर्च सेंटर जयपुर की ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को लैंगिक समानता और लैंगिक भूमिकाओं पर सर्वे को लेकर आमुखीकरण शिविर और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलसचिव परबत सिंह राठौड़ ने कहा कि वर्तमान में लैंगिक समानता की प्रबल आवश्यकता है आज के युग में हमें रूढ़िवादी सोच से बाहर आकर हमें पुरुष और महिला की भूमिकाओं पर सोचना होगा और बिना पूर्वाग्रह के सभी को अब समान अवसर मिलने चाहिए। यूनिसेफ के स्टेट कंसलटेंट जमीर अनवर ने बताया कि लैंगिक समानता पर राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को 4 आयु वर्ग 11 से 14 वर्ष 15 से 19 वर्ष 19 से 35 वर्ष और 35 से ऊपर आयु वर्ग के 304 व्यक्तियों को 1 सप्ताह में गूगल फॉर्म के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में घर-घर जाकर सर्वे करना है जिसमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर बराबर होगी और लैंगिक मुद्दों पर उनकी राय जाननी है।

बीएन विश्वविद्यालय के एनएसएस विश्वविद्यालय समन्वयक डॉ. ज्योतिरादित्य सिंह भाटी ने बताया कि सर्वे में वॉलिंटियर्स शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लैंगिक मुद्दों पर पर जानने की और जन जागरूकता लाने का प्रयास करेंगे। यह सर्वे राजस्थान के 17 जिलों में किया जा रहा है जिसमें उदयपुर जिला भी शामिल है। उदयपुर में भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय के 12 वॉलिंटियर्स का चयन इस सर्वे के लिए किय जिसकी मॉनिटरिंग विश्वविद्य प्रोग्राम ऑफिसर करेंगे। व अधिकारी डॉ. गिरधरपाल बताया कि शिविर में वॉलिं लैंगिक मुद्दों पर अपनी जिज्ञास संदर्भ व्यक्तियों से चर्चा व संदर्भ व्यक्तियों द्वारा आगामी होने वाले सर्वे के प्रत्येक विस्तृत चर्चा की गई। कार्य प्रारंभ में अतिथियों का कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सृष्टि चुंडावत ने किया। यह ज विश्वविद्यालय के ज अधिकारी डॉ. कमल सिंह दी।

उदयपुर रविवार दिनांक 16 अक्टूबर 202

लैंगिक समानता पर प्रशिक्षण कार्यक्र

जालोर. महिला कॉलेज में लैंगिक समानता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मौजूद स्वयंसेविकाएं।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जालोर. श्री राजेन्द्र सूरि,कुन्दन जैन राजकीय महिला महाविद्यालय में बुधवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में ध्लैंगिक समानताध्र विषय पर बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र ट्रस्ट की ओर से युनिसेफ के सहयोग से आमुखिकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ट्रस्ट की ओर से बजट एनालिस्ट शकील खान और नीरज महला ने संबोधित किया। खान ने बताया कि लैंगिक समानता समाज के लिए जरूरी है।

इसमें असमानता होने पर पुरूष और महिलाओं की भूमिका में बदलाव आ जाता है जो न केवल समाज के लिए बल्कि देश के लिए भी घातक मानी जाती है। एनएसएस प्रभारी डॉ. पीपाराम ने बताया कि महिलाओं को पुरूष प्रधान समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामा आर्थिक रूप से अग्रिणी निर्वाह करनी होगी। इस मोहम्मद इरफान, डॉ. चौधरी, श्विक्रम टांक, कुमार, शंकर लाल मा दवे, मुकेश कुमार, र राजकीय महाविद्यालय स्वयंसेविकाएं आरती, चौहान, मीरा, तनिषा खा उपस्थित रही।

लैंगिक भूमिकाओं पर सर्वे को लेकर प्रशिक्षण

लैंगिक समानता की प्रबल आवश्यकता

बाड़मेर @ पत्रिका. एमबीसी राजकीय, स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय बाड़मेर में राष्टीय सेवा योजना के स्वयंसेविकाओं को लैंगिक समानता और लैंगिक भूमिकाओं पर सर्वे को लेकर आमुखीकरण शिविर और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य हुकमाराम सुथार ने कहा कि वर्तमान में लैंगिक समानता की प्रबल आवश्यकता है। आज के युग में हमें रुढ़िवादी सोच से बाहर आकर पुरुष और महिला की भूमिकाओं पर सोचना होगा और बिना पूर्वाग्रह के सभी को अवसर मिलने चाहिए।बजट एनालिसिस रिसर्च सेंटर जयपुर के सन्दर्भ व्यक्ति निसारखान ने बताया कि लैंगिक समानता पर राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकाओं को सर्वे कर लैंगिक मुद्दों पर राय जाननी है। सन्दर्भ व्यवित शकील खान कुरैशी ने पूरी पारदर्शिता से सर्वे करने के लिए कहा। प्रो जितेन्द्र बोहरा ने बताया कि यह सर्वे राजस्थान के 17 जिलो में किया जा रहा है और जिसमे बाड़मेर जिला भी शामिल है। बाड़मेर के एमबीसी राजकीय कन्या महाविद्यालय की 10 स्वयंसेविकाओं का चयन किया गया। कार्यक्रम अधिकारी चेतन तिवारी ने बताया कि आमुखीकरण शिविर में एनएनएस स्वयंसेविकाओं ने लैंगिक मुद्दों पर सन्दर्भ व्यक्तियो से चर्चा की।

यूनिसेफ व बार्क टीम के आमुखीकरण शिविर का आयोजन

पाली। बांगड़ कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में यूनिसेफ व बार्क टीम द्वारा आमुखीकरण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें स्वयंसेवकों को बाल अधिकार, मानव अधिकार, महिला सशक्तिकरण तथा जेंडर संवेदनशीलता के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। प्राचार्य डॉ. कुलदीपसिंह गहलोत ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिला समन्वयक प्रो. श्यामलाल तोसावरा ने यूनिसेफ के द्वारा चलाए जाने विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। यूनिसेफ से जमीर अनवर, स्टेट कंसल्टेंट यूनिसेफ, जयपुर ने महिला सशक्तिकरण के बारे में जानकारी दी। शकील खान कुरैशी ने स्वयंसेवकों को पूरी पारदर्शिता के साथ जेंडर संवेदनशीलता प्रश्नोत्तरी की जानकारी गूगल फार्म में भरने संबंधी जानकारी दी। इस सर्वेक्षण में राजस्थान के 17 जिलों का चयन किया गया। जिसमें पाली जिले से महाविद्यालय के 10 स्वयंसेवक छात्र-छात्राओं का चयन किया गया। संदर्भ व्यक्ति नीरज महला, बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र ट्रस्ट, जयपुर द्वारा स्वयंसेवकों को लैंगिक जानकारी जुटाने संबंधी जानकारी दी। इस मौके पर एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी श्रवणसिंह, डॉ. स्वाति सोनी व डॉ. अपूर्व माथुर सहित कई लोग मौजूद रहे।